

## Result Mitra Daily Current Affairs

### जलवायु वित्त वर्गीकरण एवं भारत में हरित ऊर्जा

#### ✚ वर्त्ता में क्यों ?

- हाल ही में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिये केन्द्रीय बजट पेश किया।



- केन्द्रीय बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार “जलवायु अनुकूलन” के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण (Climate finance Taxonomy) विकसित करेगी।
- वित्त मंत्री ने “जलवायु वित्त वर्गीकरण” की घोषणा करते हुए कहा कि यह भारत की अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने की लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

#### ✚ जलवायु वित्त वर्गीकरण क्या है ?

- मुख्य रूप से जलवायु वित्त वर्गीकरण एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानकीकृत विनियमों और दिशाओं का एक समूह तैयार करता है।
- “जलवायु वित्त वर्गीकरण” जो अर्थव्यवस्था में कंपनियों एवं निवेशकों को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट से निपटने के लिये टिकाऊ एवं प्रभावशाली निवेश करने के बारे में जानकारी देता है।
- मूल रूप से टैक्सोनॉमी (Taxonomy) शब्द जीव विज्ञान (Biology) से आया है जो पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों सहित विभिन्न जीवों के नामकरण और वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जाना जाता है।
- “जलवायु वित्त वर्गीकरण” जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अर्थव्यवस्था में निवेशकों और बैंकों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है।
- जलवायु संबंधी वित्तीय उपकरणों जैसे हरित बांड आदि को वर्गीकृत करने के लिए एवं उसके मानक निर्धारित करने के लिए आमतौर पर टैक्सोनॉमी (Taxonomy) का उपयोग किया जाता है।

### ✚ “जलवायु वित्त वर्गीकरण” क्यों महत्वपूर्ण है ?

- वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहे तापमान एवं जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को नेट-शून्य अर्थव्यवस्था (Net-Zero Economy) में बदलने की आवश्यकता है।
- नेट-शून्य अर्थव्यवस्था का तात्पर्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस (GHG) की मात्रा और वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) की मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- नेट-शून्य अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए “जलवायु वित्त वर्गीकरण” विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की वैज्ञानिक तरीकों से बड़े जलवायु लक्ष्यों को संरेखित करने में मदद प्रदान करेगा।
- जलवायु संकट से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की पहली आवश्यकता निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक विकासशील देशों को जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए कम से कम 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

- UNFCCC की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार जलवायु संकट से निपटने के लिए एवं उसके लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए “जलवायु वित्त वर्गीकरण” काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगी जो निवेशकों, ऋण संस्थानों आदि के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगा।
- “जलवायु वित्त वर्गीकरण” अर्थव्यवस्था में हरित निवेश करने वाले निवेशकों को निवेश के अवसरों की तुलना करने एवं उसके पर्यावरणीय प्रभाव को मापने में भी मदद प्रदान करेगा।
- स्थानीयकृत जलवायु वित्त वर्गीकरण किसी देश की जलवायु लक्ष्यों को पेरिस समझौते एवं अन्य जलवायु प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय कारकों को ध्यान में रखकर जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग तरीके से काम करना होगा, जिसमें स्थानीय वित्त वर्गीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- “जलवायु वित्त वर्गीकरण” वैज्ञानिक आकलन के आधार पर कंपनियों द्वारा ग्रीनवाशिंग को रोकने में भी मदद करेगा।
- क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित लैंडस्केप ऑफ ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में “हरित वित्त प्रवाह” भारत की कुल विदेशी निवेश प्रवाह का मात्र 3 प्रतिशत है, ऐसे में जलवायु वित्त वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से अधिक “जलवायु निधि” लाने में मदद कर सकता है।
- भारत में कम “हरित वित्त प्रवाह” का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था के स्थायी गतिविधि के गठन में स्पष्टता की कमी है जो “जलवायु वित्त वर्गीकरण” से स्थायी गतिविधियों की गठन की स्पष्टता को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा “हरित वित्त प्रवाह” को बढ़ाने में मदद करेगा।

### **भारत में हरित वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है ?**

- जलवायु वित्त वर्गीकरण जिसे हरित वर्गीकरण (Green Taxonomy) के नाम से भी जाना जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के एक आंकड़े के अनुसार भारत की 2018 से 2030 तक लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु स्मार्ट निवेश की क्षमता है, जबकि वर्ष 2070 तक भारत की नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता के लिए अनुमानतः लगभग 10.1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

- ऐसे में अकेले सार्वजनिक निवेश के दम पर इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि एक हरित वर्गीकरण ढाँचा भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश हासिल करने एवं इसे आकर्षित करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकता है।
- भारत वर्ष 2030 तक अपने सभी वाहनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखता है, जिसके लिए लगभग 667 बिलियन डॉलर की निवेश की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भी एक अच्छा निवेश के अवसर के रूप में उभर रहा है।

### **अन्य देशों में हरित वर्गीकरण**

- वैश्विक स्तर पर कई देशों ने “जलवायु वित्त वर्गीकरण” पर काम करना शुरू कर दिया है या उसे अंतिम रूप दे दिया है।
- दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, सिंगापुर, कनाडा, मैक्सिको, चीन, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने पहले ही हरित वर्गीकरण विकसित कर लिया है।
- हरित वर्गीकरण विकसित करने वालों में यूरोपीय संघ (EU) भी शामिल है।

### **भारत द्वारा “हरित वर्गीकरण” के लिए किये गए प्रयास**

- जनवरी 2021 में भारतीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत भारत में सतत वित्त की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई।
- इस टास्क फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य सतत वित्त रोडमैप के लिए स्तंभों की स्थापना, सतत गतिविधियों के वर्गीकरण के लिए मसौदा तैयार करना एवं वित्तीय क्षेत्र द्वारा जोखिम मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करना है।
- वर्ष 2021 में ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक सदस्य के रूप में “सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम” (NGFS) में शामिल हो गया।
- NGFS यानी Network for Greening the financial system 114 केन्द्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर “हरित वित्त” के पैमाने को बढ़ाना एवं जलवायु परिवर्तन के लिए केन्द्रीय बैंकों की भूमिका के लिए सिफारिशें विकसित करना है।
- NGFS का गठन वर्ष 2017 पेरिस में “वन प्लेनेट समिट” के दौरान किया गया था।

### **भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं**

- भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

- भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कटौती करने का लक्ष्य रखता है।
- इसके अलावा भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### **भारत में हरित ऊर्जा**

- नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट-2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में चीन और रूस के बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विकास में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- भारत की 30 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित अपनी कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 42 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करता है।
- वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का ऐसा देश है, जिसने 1980 के दशक में ही गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना के साथ अपने नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की।

### **सौर ऊर्जा**

- 11 जनवरी 2010 में भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास के लिए “जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन” की स्थापना की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2022 तक 20 हजार मेगावाट ब्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित कर एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2050 तक रखा गया है।
- वर्तमान में भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 80 हजार गीगावाट है।

### **पवन ऊर्जा**

- भारत सरकार द्वारा पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2017 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- 30 नवंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 42 हजार मेगावाट है जबकि भारत की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 10 लाख मेगावाट है।

### **हरित ऊर्जा गलियारा**

- भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को “राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन” को मंजूरी दी गई।

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन की उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

#### पन बिजली

- भारत में पन बिजली की कुल दोहन क्षमता लगभग 2.5 मेगावाट है, जिसमें से केवल 30 प्रतिशत का ही वर्तमान में उत्पादन हो रहा है।

